हैं। अभी तक करीब 20 हजार जो शरणार्थी हैं जिन को बसाना बाकी है, उन के लिए जगह और इलाकों में खोज कर के और जमीन बगैरह तैयार करके बसाने की कोशिश की जा रही है।

भी बलराज मधोक: अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि जहां बसाने की कोशिश कर रहे हैं वह उन के लिए सूटेबल नहीं है। तो उत्तर भारत में ही उन को बसाने की कोशिश करेंगे?

भी ब० रा० भगत: मैंने जैसा बताया कि इन इलाकों में जैसी जमीन चाहिए और जो राज्य सरकारों से उस के लिए सुविधा चाहिए, वह नहीं मिल रही है। इसलिए मैसूर सरकार से बात की । वहां की सरकारों से बात कर के सब कुछ इंतजाम कर के तब उन को कहीं बसाया जाता है।

श्रीमती इन्बिरा गांधी: जो लोग मैसूर में बसे हैं वह कुछ समय पहले मुझ से मिलने आये थे। उन्होंने तो कहा कि वह खुशी से वहां बसे इ।

चतुर्च पंचवर्षीय योजना

*724. भी राम चरण : भी भोगेन्द्र झा : भी रिव राय :

स्वा प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या योजना आयोग ने चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना अप्रैल, 1969 से आरम्भ करने का निर्णय किया है;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) क्या सरकार को पहले ही विश्व बैंक तथा अमरीकी सरकार से इस बारे में सुझाव मिल गए वे?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (भी व० रा० भगत): (क) और (ख). इस विषय में 6 दिसम्बर, 1967 को सभा की मेज पर रखेगये दिवरण की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

श्री राम बरक: जैसा कि मंत्री जी ने बताया है वौषी पंचवर्षीय योजना उस आघार पर है जो कि 1969 में चालू होगी तो एक तो यह तीसरी योजना बजाय पंच वर्षीय योजना के सप्त वर्षीय योजना हो जायगी और दूसरे यह है कि दो साल का जो समय यह है इस में जितना स्टाफ है, वह खाली बैठा हुआ है, उन के पास कोई योजना नहीं है प्लानिंग किमशन में अनेकों कर्मचारियों को मुफ्त की तनस्वाह दी जा रही है हालांकि उन के पास काम नहीं है और वह एक-एक फाइल को लेकर 6-6 महीने बैठे रहते हैं मसलन् रिसर्च बाफि सर्स वहां पर बिलकुल सरप्लस हैं तो उन को अगर रिट्रैंच कर दिया जाय तो सरकार को कि तन धन की बचत हो सकती है?

श्री ब । रा । भगत : यह वात गलत है कि उन के पास काम नहीं है । इस की पहले ही छान बीन की गई थी और आवश्यकता से अधिक आदमी उनको दिये नहीं गये हैं ।

श्री राम चरण: वहां पर काफी सरप्लस आदमी हैं और जैसा मैंने कहा एक-एक आदमी 6-6 महीने फाइल लिये बैठा रहता है और अगर मंत्री चाहें तो ऐसे कर्मचारियों के नाम श्री मैं उन को बतला सकता हूं?

श्री व० रा० भगत: अगर नाम बसलायेंगे तो मैं इस बारे में देखूंगा।

श्री राम चरण: रिसर्च आफिसस के काम के बारे में क्या आप ने कोई स्टडी ग्रुप कायम किया है जो कि इस की जांच करे?

श्री ब॰ रा॰ भगत: में वही तो कह रहा था कि कुछ दिन पहले ही इस बात पर काफी छानबीन की गई थी कि प्लानिंग किमशन के स्टाफ में कितने आदमी हैं, कितने आदमियों की ज़क्स्रत है। बाकी जहां तक चौथी पंच-

7692

वर्षीय योजना का सावल है वह योजना सन 69 से मुरू होगी लेकिन यह कहना कि अभी उन को काम नहीं है यह ठीक बात नहीं है। जैसा कि बतलाया। गया था अभी वार्षिक योजना बन रही है, इस साल की बनी है और अभी भी राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है इस-लिए योबना कोई समाप्त नहीं हुई है. योजना का कार्य चल रहा है और इसलिए जैसा कि माननीय सदस्य समझते हैं उस में लोगों के बेकार बैठने का सवाल नहीं होता है।

श्री सरख पाण्डेय : अभी जो वक्तव्य दिया गया है उस में यह कहा गया है कि यह लड़ाई के कारण और अन्न की कमी के कारण हमारी आर्थिक स्थिति पर बहत बोझ पडा और उस से योजना के काम में देरी हुई, पिछली लड़ाई के दौरान जो सरकार ने कर लगाये और उसकी वजह से जो पैसा मिला वह भी गया और योजनाएं भी काटी गयीं तो मैं जानना चाहता हं कि बाखिर लडाई में कितना रूपमा खर्च हवा जिसकी कि वहज से हमारी योजना के ऊपर बरा प्रभाव पढ रहा है?

भी ब॰ रा॰ भगतः लडाई में जो कुछ खर्चा हुआ उस की अलग से तफसील मेरे पास नहीं है लेकिन डिफेंस बजट अगर देखेंगे तो उस से अनुमान सगा सकते हैं कि यह सब से बड़ी बात कि लड़ाई के कारण असर पड़ा वह यह है और जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा कि सारे उन देशों ने जो हमें विदेशी मुद्रा की सहायता करते वे वह सहायता करनी उन्होंने रोक दी, उन्होंने कर्जा बगैरह, ऐक्सटरनल लोन बगैरह सब रोक दिया और इस सदन में भी यह बात उठी थी कि हम इस योजना को ऐसा रूप दें कि हमारी सरकार को बाहर के देशों का सहारा लेने के लिए इंतजार न करना पड़े। इस दृष्टि से योजना को नया रूप देने की बात चली और उस पर उस दिष्ट से विचार करने की आवश्यकता पढ़ी और उस की वजह से उस के ऊपर असर पड़ा।

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR: May I know whether the pace of progress of the country has slowed down since the publication of the Draft Fourth Five Year Plan? May I also know whether while formulating the Fourth Five Year Plan beginning from 1969, the priorities and allocations would not be seriously disturbed?

SHRIB, R. BHAGAT: The slowing down has been due to the factors indicated in the statement made here earlier

भी स्वतंत्र सिंह कोठारी : माननीय प्रधान मन्त्री ने अपने स्टेटमेंट में यह कहा है कि रिसोर्सेज के हिसाब से वह प्लान को आगे बढाएंगी। तो मेरा कहना यह है कि यदि सरकारी उद्योग धंधे ठीक से और कुशलता-पूर्वक चलें. तो उन से सरकार को प्लान के लिये ... रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकेंगे। तो पब्लिक सैक्टर के उद्योग धंधों की क्षमता बढाने के लिये मंत्री महोदय या सरकार ने क्या विचार किया है, क्या कदम अभी तक उस ने उठाये हैं या उठाने के बारे में सोच रहे है?

भी ब॰ रा॰ भगत : सब से बढ़ी बात यह है कि जो पंजी लगी हुई है और धंधे हैं वह ठीक से चलें। रिससीशन की बजह से कई दिक्कतें हो गयी थीं । अब सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि उन दिक्कतों को दूर करके उद्योग धंधों को कुशलतापूर्वक चलाया जाये तभी और पंजी वापिस आयेगी।

SHRI G. S. REDDY: Have all the State plans been received by the Centre?

SHRIB, R. BHAGAT: The time schedule has been ready, and the consultation will go on till the end of this month, and by the end of this month, the State Plans are going to be finalised.

भी भीचन्य गोयलः में यह जानना चाहता हं कि ततीय पंचवर्षीय योजना के पूर्ण होने के बाद बेकारों की संख्या का क्या अनमान लगाया गया है और इस चौथी योजना का प्रारूप तैयार करते समय हम ने इस बात की क्या योजना की है कि यह बेकारों की संख्या किसी न किसी माला में फुछ कम की जाये?

भी ब॰ रा॰ भनतः अभी इस के लिए सूचना मिलने की जरूरत है क्योंकि यह तफसील की बात है।

श्री प्रकाशबीर शास्त्री: मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले प्रधान मन्त्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने आगामी पंचवर्षीय योजनाओं के सम्बन्ध में यह कहा था कि हमें ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए जिन योजनाओं का रिटर्न जल्दी हम को मिल सके तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करते समय क्या सरकार उस को नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है और दूसरी बात यह कि जिलों में जो छोटी-छोटी योजनाएं चल रही थीं इन दो वर्षों में उन योजनाओं का क्या भविष्य रहेगा?

श्री ब० रा० भगत: चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करते हुए उस में इस बात को स्वीकार किया गया था कि अब जो नई योजना बनेगी उस में इन बातों पर खास जोर दिया जायेगा।

भी प्रकासवीर शास्त्री: जिलों की योजना भी कुछ है?

श्री ब० रा० भगतः जी हां, जिलों की भी योजना है, डिस्टिक्ट प्लांस उस के लिए हैं।

श्री महाराज सिंह भारती: तीसरी योजना के समाप्त होने के बाद जो तीसरी योजना के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाई थी और इस बीच में यह चौथी योजना गुरू हो गई तो हम को यह कई साल जो अभी मिले हैं तो क्या इन सालों में उस तीसरी योजना के बकाया लक्ष्यों की पूर्ति हो जायेगी?

दूसरे जो चौथी योजना हम बनाने जा रहे हैं और जो अब तक बहस चलती रही है कि कितने की बने और कितने ही न बने, यह सब चलता रहता है तो में जानना चाहता हूं कि पुरानी जो एक रूपरेखा आई थी चौथी योजना की, चौथी योजना उन्हीं रूपरेखाओं के हिसाब से होगी या उस को बिसकुल नये सिरे से और नये ढंग से बनाया जा रहा है ? श्री ब॰ रा॰ भगत: तीसरी योजना के लक्ष्यों की पूर्ति में जो कमी रह गयी थी उस के लिए यह सब से पहला कर्त्तंच्य होता है आगे की योजना का, जीयी योजना का कि उन किमयों के पूरा करने के क्या उपाव किये जायें।

श्री महाराज सिंह भारती: चौथी योजना नहीं बल्कि उस के पहले जो यह दो, तीन साल रहते हैं उन में तीसरी योजना के बकाया लक्ष्यों की पूर्त्ति होगी या नहीं?

भी ब० रा० भगतः उन की पूर्ति करना पहला कर्तव्य होता है। श्रनाज के उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति में जो कमी रह गयी थी उस मोर सब से पहले प्राथमिकता देनी बाहिए। उसके लक्ष्य में जो कमी रह गयी है वह पूरी हो। बाकी जहाँ तक योजना के प्रारूप का सवाल है उस में 30 हजार 5 सौ करोड़ रुपये की योजना थी लेकिन मब चूंकि परिस्थिति बदल गयी है, प्लानिंग कमिशन भी बदल गया है इसलिए प्रव नये रूप से इस पर सोचा जायेगा कि उसका क्या रूप होगा लेकिन उसे इस समय बतलाना कठिन है।

श्री बैं० ना० कुरील: ग्रभी तक जो योज-नाएं चलती रही हैं उन में केवल साधन युक्त लोगों को ही लाभ हुन्ना है तो जो योजना बनेगी उसमें क्या इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि जो साधनहीन लोग देश में हैं उन को भी लाभ पहुंचे ?

श्री ब॰ रा॰ भगतः यह बहुत जरूरी चीज है ग्रीर इस पर भवश्य ध्यान दिया जायेगा।

SHRI S. KUNDU: Sometime ago the Prime Minister made a statement in the House setting out the reasons why the Fourth Plan has been shelved. In that she mentioned the Prkistani aggressicn, drought etc. The point is that instead of the Fourth Plan, we are now having three yearly plans. Are Government sure that in future also such calamities as drought or aggression will not be there? Therefore, is that the real reason for shalving the Plan? Is it not a fact that

the entire onus for the shelving of the Plan lies on the Congress Party for their indecision and inaction, that they could not decide upon what would be the policy behind the Plan and therefore to the detriment of the entire country's interests the Plan was shelved?

SHRI B. R. BHAGAT: It is not true to say that the Plan was shelved. The Prime Minister did not say that in her statement. What was said was that because of aggression the external resources were affected due to stoppage of aid and because of the drought the internal resources were vitally affected. These completely threw the entire resources aspect of the Plan out of gear. Therefore. the Plan has not been shelved nor postponed. but a new strategy of development has been evolved through annual plans. We are in a period of consolidation so that we may preserve and protect.....(laughter). The hon. Member may laugh, but facts cannot be ignored...

SHRI S. KUNDU: We had a figure of Rs. 21,000 crores....

SHRI B. R. BHAGAT: I am answering the hon. Member. What is being attempted is to....

SHRI PILOO MODY: Find excuses.

SHRI B. R. BHAGAT: ...preserve and protect what has been achieved so that when the Fourth Plan is launched, we are able to make up the loss and go forward on the expected rate of growth.

SHRI PILOO MODY: Will they at least have the cost of the champagne bottle with which to launch it?

श्रीमती सुशीला रोहतगी: घपने सीमित साधनों को घ्यान में रखते हुए तथा सुरक्षा व धन्न उत्पादन की योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए — क्या सरकार ऐसा प्रयत्न करेगी कि इनके लिये उचित साधन उपलब्ध हो सकें? इन के लिये समाज कल्याण की जो बहुत सी योजनायें चल रही हैं, उनमें से कुछ काट कर क्या सरकार उन पर पुन: क्यार करेगी तथा खाद्यान्न में घात्म निर्मरता लाने के लिये क्या सरकार इनके लिये ग्राधिक माना में साधन उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी?

श्री ब॰ रा॰ भगत: इन सारी बातों पर प्लानिंग कमीशन जरूर विचार करेगी।

SHRI N. K. SOMANI: Of late, there has been a tendency on the part of the Government of India to discuss and decide matters of vital importance outside this Parliament. When the decision to postpone the fourth plan was taken, Parliament was not consulted nor was a chance given to us to discuss it and take a decision. Another instance, which is of recent origin, was the way in which agricultural income-tax was decided upon outside the House. May I know why the Government is strengthening this tendency?

SHRI B. R. BHAGAT: Nothing new has been done.

AN HON. MEMBER: This is an old habit!

SHRI B. R. BHAGAT: The Plan has not been postponed, and whatever decision is taken by the National Development Council always comes to the House. As far as agricultural income-tax is concerned, no decision has been taken. It is being studied, and when it is necessary to ask the authority of the House, the Government will come forward. So, nothing new has been done.

श्री महाराज सिंह भारती: यह प्लान का चौथा बच्चा तीन साल बाद पैदा होना---ग्राप कहते हैं कुछ नया नहीं हुमा।

श्री रणधीर सिंह: क्या ग्रगली योजना में शहर के बजाये वेहात पर ज्यादा जोर होगा, इंडस्ट्रीज के बजाये एग्रीकल्चर पर ज्यादा एम्फेसिस डाला जायेगा, देहात में इसैक्ट्रिफिकेशन, रूरल हार्जिमन भीर एग्रीकल्चर पर ज्यादा से ज्यादा रुपया सर्च किया जायेगा भीर जितना रुपया इन कार्मों के किये पहले, दूसरे भीर तीसरे प्लान के लिये दिवा गया है, जस से दुगना रुपया एलोकेट किया जायेगा ?

श्री व० रा० भगत: देहात का जरूर स्थान किया जायेगा । माननीय सदस्य के विचार हम प्लानिंग कमीशन को भेज देंगे। SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH

SHRI HEM BARUA: Should a Member come to Parliament with a foreign cap?

MR. SPEAKER: They have presented to you and me also when we went there.

SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH: It is as much Indian as the Haryana turban and other caps on the other side.

MR. SPEAKER: Each one of us who went to Nepal has got it.

SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH: In the last seven or ten years there have been studied comments about planning in this country and also there have been comments that planning has not been as realistic as it should be, that planning has to be based on physical targets rather than monetary or financial targets. So, would the Government now make a very dispassionate and objective study instead of taking shelter under droughts, aggression etc., and look at the plan de novo, in a fresh way, and plan in a realistic way so that we achieve the desired results?

shrib. R. Bhagat: If by "realistic" is meant that needs have to be married with resources or means, that was done, because when the plan of Rs. 21,500 crores was drawn up, an estimate of the resources was also made with which the national minimum results could be achieved.

भी शिव नारायण : म्रध्यक्ष महोदय, हर प्रक्षन के ऊपर हमारे दल को, कांग्रेस पार्टी को गासियां दी जाती हैं तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि—माइ० सी० एस० के लोगों के बनाये हुए प्लान के माघार पर नहीं, बल्कि हम को प्रेक्टिकली बतायें कि जब चौथी पंच वर्षीय योजना पूरी करेंगे तो उत्तर प्रेश को जिसे पिखले तीन प्लानों में नैगलैक्ट किया गया है, उस की पूर्ति करेंगे या नहीं ?

SHRI PILOO MODY: Sir, I object to any Congressman trying now to shift the blame on to the ICS. (Interruption). Finally, after they have run out of all excuses, now he wants to blame it on the ICS.

भी शिव नारायण : हम वम्बई से नहीं भाते हैं, हमारे यहां स्पैक मनी नहीं है। भी व ः रा ० भगतः यह पार्टी का प्लान नहीं है, यह प्लान पालियामेंट का बनाया हुन्ना है।

भी शिव नारायण: घष्यक्ष महोवय, हमें जबाब नहीं मिला । पिछली तीन योजनाम्रों में उत्तर प्रदेश को टोटली नैगलैक्ट किया गया है, उस को पूरा करेंगे या नहीं?

अष्यक्ष महोदय: जवाब दिया है, भाई।

भी शिव नारायणः प्रध्यक्ष महोदय, हम भी इस हाउस को रिप्रजेन्ट करते हैं, जनता हम से पूछती है ? हमें साफ जबाब मिलना चाहिये।

श्री ब ॰ रा॰ भगत: उत्तर प्रदेश या दूसरे जितनें भी पिछड़े हुए प्रदेश हैं, उन पर पूरा भ्यान दिया जायेगा।

SHRI INDRAJIT GUPTA: In the statement which the hon. Prime Minister made on the 8th December, listing the reasons according to her, why it has become necessary to have this sort of Plan post ponement or holiday, may I know why there is no mention in it at all of the devaluation of the rupee? Is it because they think that it will not have any effect? Secondly, in view of the fact that our planning has been dangerously overdependent on foreign aid, has the Minister's attention been drawn to yesterday's news that the United States Congress has decided to cut down foreign aid drastically, to what they call, on all-time low, and in view of this, does he still think that they will be able to start this fourth Plan again from 1969?

SHRI B. R. BHAGAT: Devaluation is not the reason for postponening the Plan because it does not in any way affect the resources position. That is the answer for the first part. As for the over-dependence on foreign loans, the strategy of our Plan is to progressively reduce the quantum of foreign aid that is necessary for development and growth. But even there, (Interruption), it is much less than in any other developing economy. What was there by way of aid, even that relates to the crucial period. The percentage may be as low as 10 percent or even less. But it is

enough because it goes to a very vital sector of the economy, and stoppage of this aid dislocates the entire Plan as such. That is the reason.

SHRI S. R. DAMANI: While welcoming the postponement of the Plan to 1969, I want to know whether the targets fixed in the draft Plan will be altered or be maintained, and whether consideration will be given to the public sector projects which are running with reduced capacity, whether they will get preference.

SHRIB. R. BHAGAT: The new Planning Commission is giving an entirely new look to this and it will come to its own conclusion about the target, the resources and the priorities.

भारत सेवक समाज को प्रनुदान

*725. डा॰ सूर्य प्रकाश पुरी : श्री रामावतार शर्मा : श्री शिव कुमार शाली : श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या प्र<mark>षान मन्त्री यह ब</mark>ताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने भारत सेवक समाज को किसी न किसी रूप में अनुदान देने का निष्चय किया है हालांकि लोक लेखा समिति ने इस संगठन की हाल में श्रालोचना की है:
- (स) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि कुछ सम्बन्धित व्यक्ति इस समाज के लेन-देन सम्बन्धी मामलों को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं; भौर
- (ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में जांच करने का है ?

THE DEPUTY MINISTER (DR. SAROJINI MAHISHI): (a) No grant has been released to the Samaj since November 1966. Government have not yet taken any decision about future releases and are considering the latest report of the Public Accounts Committee received last month.

- (b) No such complaint or allegation has come to notice.
 - (c) Does not arise.

डा॰ सूर्य प्रकास पुरी: प्रध्यक्ष महोवय, भारत सेवक समाज की स्थापना पं॰ जवाहर लाल नेहरू ने जिस उद्देश्य से की थी, उस से हट कर वह प्रस्य कांग्रेसी समाज सेवी संस्थाघों के सदृश्य हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार का अनुदान भारत सेवक समाज को मिसता रहा है, उसी प्रकार का अनुदान प्रस्य भौर कितनी संस्थाघों को केन्द्र की घोर से मिसता रहा है। दूसरे—ऐसे कितने राज्य हैं, जिन्होंने भारत सेवक समाज को, जो अनुदान वह पहले दिया करते थे वह बन्द कर दिया है? तीसरे—क्या भारत सेवक समाज ने पी० ए० सी० की रिपोर्ट पर सभी तक अपनी टिप्पणी दी है या नहीं?

DR. SAROJINI MAHISHI: It is a wrong impression that undesirable people are associated with the Bharat Sewak Samaj. The objective of the Samaj is very laudable, i.e. to provide employment to the people and to create voluntary services. Therefore, it is a wrong impression to think that undesirable people and matters are associated with this institution. Secondly, I require notice as to how many States have stopped giving aid to the Bharat Sewak Samaj.

Thirdly, he asked which other organisations similar to Bharat Sewak Samaj are receiving grant. The impression carried by the hon. Member is wrong, that all institutions which have got laudable objectives and which are meant for constructive work are receiving some aid.

डा॰ सूर्य प्रकाश पुरी: मेरे प्रक्त का एक भाग यह भी था कि पी॰ ए॰ सी॰ की रिपोर्ट के ऊपर भारत सेवक समाज ने अपनी टिप्पणी की है अथवा नहीं की है?

DR. SAROJINI MAHISHI: The 34th Report of the PAC (Third Lok Sabha) and 9th Report of the PAC (Fourth Lok Sabha) deal with use of funds given to Bharat Sewak Samaj. The Department of